राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 143

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 1 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

टीम इंडिया में दखल पर अनुष्का ने तोड़ी चुप्पी

>> 14

सरोकार

युवाओं को रोजगार दे रही मुरादाबादी बिरयानी

रामपुर : बिरयानी का नाम सुनते ही नॉनवेज के शौकीनों के मुंह में पानी आ जाता है।

मुरादाबादी बिरयानी की अपनी पहचान है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत अनेक शहरों में मुरादाबादी बिरयानी खूब बिक रही है। युवाओं ने इसे रोजगार का साधन बना लिया है। (पेज-10)

जागरण विशेष

फूलों के खेतों में लिविंग कॉटेज से लेकर स्वीमिंग पूल तक

मेरठ : 'पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ गन्ना की खेती' के मिथक को प्रगतिशील किसान ने तोड़ दिया।

फल-फूल और सब्जियों की खेती के अलावा खेतों में ही सुंदर नेचर पार्क भी बनाया, जिसमें पर्यटकों की भीड़ जुटती है। (पेज-10)

भारतीय पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की हुई जासूसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टैंट मैसेजिंग कंपनी वाट्सएप ने गुरुवार को कहा कि इजरायली स्पाइवेयर 'पेगासस' के जरिए अनाम इकाइयों ने भारतीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की। कंपनी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर करीब 1,400 वाट्सएप उपयोगकर्ताओं की जासूसी की गई है। केंद्र सरकार ने इस मामले में वाट्सएप से जवाब मांगा है।

वाट्सएप ने यह नहीं बताया है कि किसके कहने पर पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए। कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि भारत में इस स्पाइवेयर हमले से कितने पत्रकार और कार्यकर्ता प्रभावित हुए। लेकिन उसके प्रवक्ता ने कहा कि इस सप्ताह हमने जिन लोगों से संपर्क किया है उनमें भारतीय उपयोगकर्ता भी शामिल हैं।

वाट्सएप ने कहा है कि मई में उसे ऐसे अत्याधुनिक साइबर हमले का पता चला जिसमें उसकी वीडियो कालिंग प्रणाली को हैक कर उसके उपयोगकर्ताओं को मालवेयर भेजा गया।

- वाट्सएप ने राज खोला, इजरायली स्पाइवेयर 'पेगासस' ने की जासूसी
- वाट्सएप ने कहा, कंपनी को मई में इसके बारे में चला था पता
- सरकार ने मैसेजिंग एप कंपनी से चार नवंबर तक मांगा जवाब

यूजरों को दी थी जानकारी

कंपनी ने कहा है कि उसने लगभग 1,400 उपयोगकर्ता को विशेष संदेश भेजकर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि दुनियाभर में वाट्सएप के लगभग 1.5 अरब यूजर हैं। इनमें भारत के करीब 40 करोड़ लोग शामिल हैं।

इजरायली कंपनी पर ठोका मुकदमा

वाट्सएप ने कहा है कि इस साइबर हमले के लिए उसने इजरायली निगरानी फर्म एनएसओ ग्रुप पर मंगलवार को कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में केस दर्ज कराया है। कहा जा रहा है कि इसी कंपनी की तकनीक की मदद से अज्ञात इकाइयों ने जासूसी के लिए दुनिया के 1400 वाट्सएप यूजरों के फोन हैक किए। इनमें राजनयिक, पत्रकार और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

इजरायली कंपनी ने आरोप नकारे : इजरायल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने अज्ञात इकाइयों को तकनीकी मुहैया कराने के आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि वह आतंकवाद और गंभीर अपराध से निपटने के लिए सिर्फ लाइसेंस वाली सरकारी खुफिया एजेंसियों को ही अपनी तकनीक उपलब्ध कराती है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार निजता की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध

इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार अपने नागरिकों की निजता की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, सरकार

भारतीय नागरिकों की निजता के हनन को लेकर चिंतित है और वाट्सएप से पूछा गया है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ और वह भारतीय नागरिकों की निजता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। प्रसाद ने कहा, किसी भी तरह की निगरानी के लिए सुरक्षा एजेंसियां एक निश्चित प्रोटोकॉल का पालन करती हैं। यह कदम केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में ही उठाया जाता है। मंत्रालय ने इस मामले में वाट्सएप से चार नवंबर तक जवाब देने को कहा गया है। वहीं, गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने जासूसी संबंधी खबरों को सरकार की छवि खराब करने की कोशिश बताते हुए कहा, अगर कोई लोगों की निजता के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरकार शुरू से ही सोशल मीडिया कंपनियों खासतौर पर वाट्सएप पर इस बात का दबाव बना रही है कि वह मैसेज डिक्रिप्ट करने के बजाए उसके स्रोत का पता लगाने में मदद करे। लेकिन वाट्सएप निजता में हनन का हवाला देकर ऐसा करने से बचती रही है।

सरकार का स्पाइवेयर पेगासस खरीदने से इन्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने इजरायली स्पाइवेयर पेगासस खरीदा है। सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई सूचना उसके पास नहीं है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 23 अक्टूबर 2019 को ही सौरव दास नाम के एक व्यक्ति ने आरटीआइ के जरिए केंद्र सरकार से पेगासस स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने संबंधी जानकारी मांगी थी। यह सॉफ्टवेयर फोन पर मैसेज पढ़ने, पासवर्ड एकत्र करने और फोन की लोकशन जानने में माहिर माना जाता है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को भेजे अपने जवाब में ऐसी कोई भी सूचना उपलब्ध होने से इन्कार किया है। मंत्रालय के सीपीआइओ के हस्ताक्षर से भेजे गए अपने जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रार्थी संतुष्ट न होने की स्थिति में एक महीने के भीतर एपीलैट अथॉरिटी में अपील दाखिल कर सकता है।

न्यूज गैलरी

सिटी न्यूज ▸ पृष्ठ 2

फांसी के तख्ते के और करीब पहुंचे निर्भया के गुनहगार

नई दिल्ली : देश को झकझोर देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म कांड के गुनहगार फांसी के तख्ते के और करीब पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही दोषियों की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर चुका है। अब सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा माफ किए जाने पर ही वे फांसी के फंदे से बच सकते हैं, अन्यथा मौत की सजा तय है।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 5

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बने केंद्रशासित प्रदेश

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर व लद्दाख गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश बन गए। श्रीनगर के राजभवन में जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू और लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर राधाकृष्ण माथुर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही विकास का नया दौर शुरू होगा।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

आरसेप पर अंतिम फैसले से पहले भारत कशमकश में

नई दिल्ली : सोमवार को आसियान के 10 देशों समेत 16 देशों के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते यानी आरसेप पर अंतिम फैसला होना है, लेकिन भारत इसे लेकर कशमकश में है। सभी देशों के अधिकारी बैंकॉक में मंत्रणा कर रहे हैं। भारत चाहता है कि कृषि उत्पादों व सेवा उद्योग पर उसकी चिंताएं अंतिम मसौदे में शामिल की जाएं।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

जाधव मामले में पाकिस्तान ने किया वियना संधि का उल्लंघन

संयुक्त राष्ट्र : अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के अध्यक्ष जज अब्दुलकावी यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में वियना संधि का उल्लंघन किया। यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जाधव को वियना संधि के तहत सभी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

चीन ने बढ़ाया तनाव, भारत ने याद दिलाया कश्मीर पर अवैध कब्जा

रिश्तों में तल्खी ▸ पहले बीजिंग फिर पाक ने अनुच्छेद 370 हटाने को बताया गैरकानूनी

भारत ने कहा, आंतरिक मामलों में किसी भी देश को बोलने का हक नहीं

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

ठीक 20 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच मामल्लपुरम में द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने के लिए जो सहमति (चेन्नई कनेक्ट) बनी थी वह हवा होती दिख रही है। इसके पीछे कश्मीर सबसे बड़ी वजह के तौर पर सामने आया है। गुरुवार को जब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नया सवेरा हो रहा था तो चीन और पाकिस्तान ने एक सुर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को गैरकानूनी करार दिया। भारत ने पाक के बयान पर तो प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन चीन के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए चीन को याद दिलाया कि उसने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर

रवीश कुमार — फाइल फोटो

कब्जा कर रखा है और पाक के साथ मिलकर कश्मीर के एक हिस्से पर सड़क बना रहा है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और उसके हिस्से को केंद्र सरकार के अधीन लेने का फैसला पूरी तरह से गैरकानूनी है। भारत ने इस फैसले से चीन के एक हिस्से को अपने में मिलाने का काम किया है और इससे चीन की संप्रभुता को चुनौती दी गई है। चीन इसकी भर्त्सना करता है। भारत ने जिस तरह यह कदम उठाया है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। भारत का यह कदम इस सच्चाई को नहीं बदल सकता कि वह हिस्सा चीन के नियंत्रण वाला है। चीन भारत से आग्रह करता है कि वह फैसले को तुरंत बदले और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए पूर्व में की गई संधियों का पालन करे ताकि सीमा विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से हल हो सके।' वहीं, पाक का कहना था कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का मकसद जनसांख्यिकी ढांचे को बदलना है। पाक विदेश मंत्रालय के अनुसार, 'कश्मीर की स्थिति में बदलाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और भारत-पाक के बीच समझौतों खासकर शिमला समझौते का उल्लंघन है। कश्मीर अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य विवादित क्षेत्र है और भारत से इसे बदल नहीं सकता।'

चीन के बयान के कुछ ही घंटे बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'चीन इस बारे में भारत की स्थायी नीति से भली भांति परिचित है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के इलाके को लेकर भारत का फैसला पूरी तरह से आंतरिक है। इन मुद्दों पर हम चीन या किसी भी दूसरे देश की तरफ से टिप्पणी की उम्मीद नहीं करते। वैसे चीन भी जम्मू-कश्मीर के बड़े इलाके पर कब्जा किए हुए है। साथ ही 1963 में किए गए चीन-पाक सीमा समझौते के तहत चीन ने भारत के एक हिस्से को भी गैरकानूनी तरीके से कब्जे में ले रखा है। इस हिस्से को पाक ने चीन को सौंपा है।' भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की याद भी दिलाई जो जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर बनाया जा रहा है। कहा, चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह हिस्सा भी पाकिस्तान के पास 1947 से गैरकानूनी तरीके से है। जहां तक सीमा विवाद सुलझाने का मामला है तो भारत हमेशा से इसे शांतिपूर्ण तरीके और बातचीत से सुलझाने का समर्थक रहा है। इसको लेकर 2005 में दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी और हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में भी ऐसी समझ बनी थी। दोनों देश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भी तैयार हुए हैं।

अमेरिका से जुड़ा है तनाव का सिरा पेज>>3

राष्ट्रगान के दौरान बैठी रह सकेंगी जर्मन चांसलर एंजिला मर्केल

नई दिल्ली : जर्मनी की चांसलर एंजिला मर्केल शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक कार्यक्रम में दोनों देशों के राष्ट्रगान के दौरान बैठी रह सकेंगी। मर्केल की बीमारी को देखते हुए जर्मनी ने इसके लिए विशेष अनुरोध किया था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मर्केल को अनुमति देने के लिए राष्ट्र गान से जुड़े आदेश के कुछ खास प्रावधानों को लागू किया जाएगा। (पेज-3)

राम मंदिर पर फैसले के लिए खुद को तैयार कर रहा संघ

नई दिल्ली : अयोध्या में राम मंदिर पर किसी भी फैसले के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को तैयार कर रहा है। संघ का मानना है कि नवंबर मध्य तक आने वाला कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में होगा। हालांकि, विपरीत फैसला आने की स्थिति के लिए भी वह रणनीति पुख्ता कर लेना चाहता है। छतरपुर में चल रही संघ परिवार की तीन दिनी बैठक में गुरुवार को दूसरे दिन भी मंदिर का मुद्दा छाया रहा। (पेज-7)

'जानबूझकर नहीं लंबित रहा अयोध्या मामला'

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि के मुकदमे को सुनने वाले न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे अयोध्या विवाद आठ वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के सवाल पर कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा जानबूझकर हुआ। इसके पीछे और कई कारण हो सकते हैं। जैसे मुकदमे से जुड़े रिकार्ड के अनुवाद में बहुत वक्त लगना, सुनवाई करने वाली पीठ का गठन न हो सकना आदि। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में जस्टिस बोबडे से पूछा गया कि क्या फैसला लिखने में न्यायाधीशों की अपनी आस्था और विश्वास का प्रभाव होता है तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। न्यायाधीश इस सबसे ऊपर उठ कर मुकदमे के तथ्यों और कानून को देखकर फैसला देते हैं। ये चीजें उनके आड़े नहीं आतीं।

जस्टिस एसए बोबडे इतना जरूर मानते हैं कि अयोध्या के मुकदमे की व्यापकता उसका असर और अवधि आदि सब मिला कर देखा जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा है।

- भावी सीजेआइ बोले-नहीं लगता किसी कोर्ट ने ऐसा मामला सुना होगा
- कहा-लोग देश की न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखें

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। — जागरण

मुकदमे का महत्व बताते हुए वह कहते हैं कि उनकी जानकारी में नहीं है कि दुनिया की किसी अदालत ने इस तरह का मुकदमा सुना होगा। हालांकि मामले में फैसला लंबित होने के कारण मुकदमे की मेरिट पर बोलने से परहेज कर गए।

भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए जस्टिस एसए बोबडे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के सेवानिवृत होने के बाद 18 नवंबर को 47वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। जस्टिस बोबडे अयोध्या राम जन्मभूमि का मुकदमा सुनने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा हैं। इस मामले में 17 नवंबर से पहले फैसला आना है क्योंकि उसी दिन जस्टिस गोगोई सेवानिवृत हो रहे हैं।

सुनवाई के सीधे प्रसारण पर होगा विचार : सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के सीधे प्रसारण के मुद्दे पर उनका कहना है कि यह महत्वपूर्ण मामला है और अभी तक उन्होंने इस मामले को जांचा परखा नहीं है। अब वे इसे देखेंगे। अयोध्या मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसके सजीव प्रसारण की मांग उठी थी लेकिन बात बनी नहीं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इसे शुरू करने की व्यवस्था पर रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी थी।

संतुलन कायम रखने की जरूरत पेज>>7

जम्मू-कश्मीर में दीवार की तरह काम कर रहा था अनुच्छेद 370 : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के केवडिया में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। — एएनआइ

केवडिया (गुजरात), प्रेट्र : राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 एक दीवार की तरह काम कर रहा था और उसने राज्य में सिर्फ आतंकवाद को ही पोषित किया। साथ ही उन्होंने भारत की विविधता में एकता को देश के दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती करार दिया।

सरदार पटेल की 144वीं जयंती पर यहां 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नई व्यवस्था का मकसद जमीन पर लकीर खींचना नहीं बल्कि विश्वास की मजबूत कड़ी का निर्माण करना है।' मोदी ने कहा कि अनुच्छेद-370 हटाने के केंद्र के फैसले को वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के चरणों में समर्पित करते हैं। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर में एक दीवार की तरह था जो अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थी। मोदी ने कहा, 'मैं सरदार पटेल को बेहद विनम्रता से यह बताने आया हूं कि दीवार गिरा दी गई है।' उन्होंने बताया कि राज्य में आतंकवाद के तीन दशक के दौर में 40 हजार से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल से प्रभावित उनकी सरकार देश के भावनात्मक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण के लिए काम कर रही है। इसके बगैर 21वीं सदी में शक्तिशाली भारत की कल्पना मुश्किल है। पूर्वोत्तर भी अब अलगाववाद से जुड़ाव की ओर बढ़ रहा है क्योंकि दशकों पुरानी समस्याएं अब समाधान के करीब हैं।

पाक पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जो भारत के खिलाफ लड़ाइयां नहीं जीत सके वे अलगाववाद और आतंकवाद फैलाकर भारत की एकता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सदियों तक कोशिश करने के बावजूद कोई भी हमें मिटा नहीं सका या हरा नहीं सका। विविधता में एकता हमारा गौरव है और हमारी पहचान है। इतनी विविधता के बावजूद हमारी एकता से दुनिया आश्चर्यचकित है। भारत दुनिया के अन्य देशों से अलग है। हम अपनी विविधता से खुश हैं। हम विविधता में विरोधाभास नहीं बल्कि एकता देखते हैं। जब हम विभिन्न समुदायों और धर्मों की आस्था और परंपराओं का सम्मान करते हैं तो प्रेम और लगाव बढ़ता है। जब सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाने का मिशन शुरू किया था तो एकता की भावना ने कई शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। सदियों पहले भारत को चाणक्य ने एकजुट किया था और उसके बाद पटेल ने यह काम किया। इस मौके पर पुलवामा हमले में शहीद जवान नसीर अहमद की पत्नी ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की प्रतिकृति भेंट की।

शाह बोले, पटेल के प्रयास से बना देश का वर्तमान मानचित्र पेज>>6

हाल बेहाल

1998 से 2016 के बीच सात राज्यों में सात साल कम हुई भारतीयों की आयु, उत्तर भारत में प्रदूषण बाकी देश के मुकाबले तीन गुना अधिक जानलेवा, सर्वाधिक प्रभावित हरियाणा, उप्र, दिल्ली, पंजाब समेत सात राज्यों में रहती है देश की 40 फीसद आबादी

जहरीली हवा का असर, घटी गंगा किनारे रहने वालों की उम्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

वायु प्रदूषण यानी जहरीली हवा अब लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। एक अध्ययन ने बताया है कि उत्तर भारत में जहरीली हवा के कारण गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वाले भारतीयों की आयु सात साल तक कम हो गई है। 1998-2016 के बीच हुए शोध में कहा गया है कि उत्तर भारत में प्रदूषण बाकी भारत के मुकाबले तीन गुना अधिक जानलेवा है। इस अध्ययन में सबसे अधिक प्रदूषित दिल्ली को बताया गया है। यहां 2016 के दौरान पीएम 2.5 का स्तर 114 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर रहा।

उत्तर भारत में 48 करोड़ से अधिक आबादी या कहें कि देश की 40 फीसद जनसंख्या गंगा नदी के किनारे रहती है। अत्यधिक दूषित हवा वाले यह राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हैं। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट के अनुसार, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक 2016 आते-आते क्षेत्र में वायु प्रदूषण 72 फीसद तक बढ़ गया। इसके चलते उत्तर भारत में रहने वालों का जीवन 3.4 साल था, जो अब 7.1 साल तक कम होने लगा है।

शोध में कहा गया है कि गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वालों की आयु भारत के अन्य इलाकों में रहने वालों की आयु की अपेक्षा तीन गुना कम हो रही है। एक्यूएलआइ के अनुसार, भारत अगर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लक्ष्यों को हासिल कर लेता है और मौजूदा प्रदूषण में 25 फीसद की कटौती कर लेता है तो वायु गुणवत्ता में इस कदर सुधार होगा कि भारतीयों का औसत जीवन 1.3 साल बढ़ जाएगा। मैदानी इलाकों के लोगों की आयु दो साल बढ़ जाएगी। हिंदी बेल्ट के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के एक कार्यक्रम में असम के सांसद गौरव गोगोई ने कहा, वह इस विषय में एक प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पेश करेंगे। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उनका नया स्वच्छ वायु (संशोधन) अधिनियम उनकी सर्वोच्च वरीयता होगा। इसी कार्यक्रम में दिल्ली के अस्पताल गंगाराम के लंग्स स्पेशलिस्ट डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि दिल्ली में जनस्वास्थ्य की आपात स्थिति है। अब समय आ गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए।

नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मास्क पहनकर अभ्यास करते लिटन दास। — एएनआइ

मास्क पहनकर अभ्यास

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को टी-20 सीरीज खेलने के लिए आई बांग्लादेश टीम के बल्लेबाज लिटन दास ने अरुण जेटली स्टेडियम में मास्क पहनकर अभ्यास किया। ध्यान रहे 2017 में टेस्ट मैच के दौरान भी कुछ ऐसे ही हालत थे उस समय श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने मास्क पहनकर मैच खेला था। वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंचने की वजह से 20 मिनट तक खेल रोकना पड़ा था। (पेज-14)

शरद पवार से मिले संजय राउत और कांग्रेस नेता

मुंबई, एजेंसियां : महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना के बीच सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध के बीच अन्य विकल्पों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गईं हैं। इस क्रम में गुरुवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने राकांपा सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थरोट, वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण ने भी शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की।

पवार से राउत की मुलाकात ने सूबे में गैरभाजपा सरकार की अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि राउत ने चुनाव परिणाम की घोषणा वाले दिन (24 अक्टूबर) भी पवार से भेंट की थी। वहीं, कांग्रेस नेताओं की पवार से मुलाकात के बारे में सूत्रों ने बताया कि उन्होंने वर्तमान राजनीति हालात के मद्देनजर अपने गठबंधन की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। इसके बाद तीनों नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। बताते हैं कि पवार ने ही उनसे इस बारे में सोनिया से बात करने को कहा है। कांग्रेस ने गुरुवार को अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ भी बैठक की। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे।

- मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली रवाना
- कांग्रेस-राकांपा के समर्थन से शिवसेना सरकार गठन की अटकलें

एकनाथ शिंदे बने शिवसेना विधायक दल के नेता

मुंबई : महाराष्ट्र में विस चुनाव नतीजों की घोषणा के एक हफ्ते बाद भी सरकार गठन पर गतिरोध जारी है। इस बीच चौथी बार विस सदस्य बने एकनाथ शिंदे को गुरुवार को शिवसेना विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फड़नवीस के दिए बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा, हम मित्रपक्ष को मित्रपक्ष मानते हैं शत्रुपक्ष नहीं। (पेज-4)

इससे पहले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चह्वाण ने एक बार फिर शिवसेना को उकसाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। इसके बावजूद यदि वह सरकार बनाने में अक्षम रहती है तो दूसरे बड़े दल के रूप में शिवसेना को मौका मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि शिवसेना सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगती है तो हम कांग्रेस आलाकमान से इस पर विचार करने को कहेंगे। पृथ्वीराज चह्वाण चुनाव ने परिणाम आने के दिन भी कहा था कि शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा की संयुक्त सरकार बन सकती है।

हालांकि राकांपा के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल एक दिन पहले ही कह चुके हैं कि सरकार बनाने का जनादेश भाजपा-शिवसेना गठबंधन को मिला है। यदि उनमें कोई मतभेद है तो उन्हें आपस में सुलझाकर राज्य को स्थिर सरकार देने का प्रयास करना चाहिए। पटेल का साफ कहना था कि राकांपा किसी को समर्थन देने के बजाय विपक्ष में बैठेगी। बता दें कि 2014 के चुनाव के बाद 288 सदस्यीय विधानसभा में जब 122 विधायकों वाली फड़नवीस की अल्पमत सरकार ने शपथ ली थी तो राकांपा ने उसे बाहर से समर्थन दिया था। जबकि इस बार भाजपा ने 105, शिवसेना ने 56, राकांपा ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल की है। (पेज-4 भी देखें)